# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी— श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

| मिसल संख्याः | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 244 / अपील / 2017 | 08.11.2017 | 11.05.2018 |

देवलाल आ0 कल्याण जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुजरिया का खेड़ा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राजस्थान)

— अपीलांट

— बनाम —

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी (राज0)

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24.03.2017
नायब तहसीलदार, नैनवां
अन्तर्गत धारा 22 रा0 उप निवेशन अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :—

अपीलांट की ओर से — श्री महावीर मीणा, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से — पेरोकार सरकार

## :— निर्णय :—

यह अपील नायब तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 02 बीघा किस्म नहरी—II वाके ग्राम गुजरिया का खेड़ा तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये धारा 22 रा0 उप निवेशन अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 250/— रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु

स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है एवं आदेश न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया फिर भी अपीलान्ट की तामील मान ली गई है। जवाब व बहस का अवसर नहीं दिया गया है। बकाया राशि जमा करा दी गई है। अपीलान्ट का कोई राजस्व बकाया नहीं है। अतिक्रमित भूमि से कब्जा छोड़ दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये निर्णय पारित किया गया है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अपीलान्ट को निर्णय पारित करने से पहले पश्चातवर्ती साबित करने का कोई शहादत व दस्तावेज नहीं लिये है। पश्चातवर्ती साबित किये बिना सजा का आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय नहरी–II भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व रिपोर्ट पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा छोड़ने बाबत् पटवारी रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने बाबत् कोई दस्तावेज नहीं लिये हैं, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ

न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को गत वर्ष मिसल नं. 471 दिनांक 14.10.2017 द्वारा निर्णय पारित किया जाकर बेदखल किया गया था तथा पटवारी रिपोर्ट व पटवारी बयान से भी अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होता है। अपीलान्ट विवादित भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/5/18

(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)